



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 6 मई, 1986/16 वैशाख, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 6 मई, 1986

क्रमांक एल० एल० आर० (डी०) (6)9/86.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 3 मई, 1986 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड विधेयक, 1986 (1986 का विधेयक संख्यांक 6) को 1986 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में संविधान

के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव।

1986 का अधिनियम संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1986

(राज्यपाल द्वारा 3 मई, 1986 को यथा अनुमोदित किया गया)

हिमाचल प्रदेश राज्य में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना और गठन और तत्संबद्ध विषयों के वास्ते उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1986 है।

संक्षिप्त
नाम, विस्तार
और प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं

- (क) “संबद्ध संस्था” से अधिनियम या तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी पाठ्यक्रम या किन्हीं पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में बोर्ड से संबद्ध कोई संस्था अभिप्रेत है ;
- (ख) “बोर्ड” से धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (ग) “उप-विधियों” से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई उप-विधियां अभिप्रेत हैं ;
- (घ) “केन्द्र” से बोर्ड द्वारा अपनी परीक्षाएं लेने के प्रयोजनार्थ नियत संस्था या स्थान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उससे संलग्न या अनुलग्न परिसर भी है ;
- (ङ) “प्रमाण-पत्र” से बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति को, संबद्ध संस्था में, समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित पाठ्यक्रमों को सफलता-पूर्वक पूरा करने पर दिया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है ;
- (च) “अध्यक्ष” से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (छ) “डिप्लोमा” से बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति को संबद्ध संस्था में समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित पाठ्यक्रमों को सफलता-पूर्वक पूरा करने पर दिया गया डिप्लोमा अभिप्रेत है ;
- (ज) “निदेशक” से निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;
- (झ) “औद्योगिक प्रशिक्षण” से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रों को प्रदान किया गया, प्रशिक्षण अभिप्रेत है ;

- (ज) "संस्था" से तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था अभिप्रेत है ;
- (ट) "वीक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो केन्द्र के अधीक्षक को केन्द्र में होने वाली परीक्षा के संचालन और अधीक्षण में अधीक्षक की सहायता करता है और इसके अन्तर्गत परियोजना परीक्षा के सम्बन्ध में परियोजना प्रेक्षक भी है ;
- (ठ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी है ;
- (ड) "शासकीय राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;
- (ढ) "प्रधानाचार्य" से संस्था का प्रधान अभिप्रेत है ;
- (ण) "विनियम" से बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;
- (त) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ;
- (थ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ;
- (द) "केन्द्र अधीक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे बोर्ड द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन और अधीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त अधीक्षक और सहयुक्त अधीक्षक भी हैं ;
- (ध) "तकनीकी शिक्षा" से तकनीकी संस्थाओं में छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा अभिप्रेत है ; और
- (न) "उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

बोर्ड की
स्थापना ।

3. (1) राज्य सरकार द्वारा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, "हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड" से जातव्य एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी और ऐसी अधिसूचना इस तथ्य के होते हुए भी कि सदस्यों के एक या अधिक स्थान अभी तक भरे नहीं गए हैं, जारी की जा सकती है ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निगमित बोर्ड शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा रखने वाला एक निगमित निकाय होगा जिसके पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों सम्पत्तियों को अर्जित और धारण करने और इस द्वारा धारित किसी सम्पत्ति को अन्तरित करने और संविदा करने और इसके गठन के प्रयोजनार्थ अन्य सभी आवश्यक कार्य करने की शक्ति होगी और यह वाद ला सकेगा या इस पर इसके निगमित नाम से वाद लाया जा सकेगा ।

बोर्ड का
गठन ।

4. (1) बोर्ड, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा, अर्थात् :—

I. पदेन सदस्य :

- (i) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा से तत्समय सम्बन्धित मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि ;
- (ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की उत्तर क्षेत्रीय समिति का एक प्रतिनिधि ;
- (iii) सचिव (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार ;

- (iv) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार ;
- (v) श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ;
- (vi) उद्योग निदेशक, हिमाचल प्रदेश ;
- (vii) रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ;
- (viii) प्रधानाचार्य, प्रादेशिक इंजीनियरी महाविद्यालय, हर्मासपुर, हिमाचल प्रदेश ;

II. निर्वाचित सदस्य :

- (ix) हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा विहित रीति से निर्वाचित दो सदस्य ;

III. नाम निर्दिष्ट सदस्य :

- (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे)
- (x) हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग का एक मुख्य अभियन्ता ;
- (xi) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का एक मुख्य अभियन्ता ;
- (xii) दो उद्योगपति ;
- (xiii) राज्य के बहुशिल्प-शिक्षणालय का एक प्रधानाचार्य ;
- (xiv) राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का एक प्रधानाचार्य ;
- (xv) ऐसे हितों का, जिन्हें अन्यथा प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक सदस्य ।

IV. सहयोजित सदस्य :

- (xvi) बोर्ड द्वारा तकनीकी शिक्षा में विशेषज्ञीय और विस्तृत जानकारी रखने वाला सहयोजित एक सदस्य ।

(2) उप-धारा (1) के उप-खण्ड (iii), और (iv) में उल्लिखित सदस्यगण बोर्ड की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने की बजाये अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारीगण उस विशेष बैठक को, जिसके लिए उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है, कार्यवाही में भाग लेने और ऐसी बैठक में मत देने के भी हकदार होंगे ।

5. बोर्ड का मुख्यालय, राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित स्थान पर होगा ।

बोर्ड का मुख्यालय ।

6. (1) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी ।

(2) यदि कोई निर्वाचित सदस्य, किसी कारण उस विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है, जिससे वह निर्वाचित हुआ था, तो वह सदस्य नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा ।

सदस्यों की पदावधि और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।

(3) इस धारा में किसी बात के अन्तर्निहित होते हुए भी, कोई पदावरोही सदस्य, जब तक सरकार अन्यथा निदेश न दे तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसके उत्तरवर्ती का निर्वाचन, नामनिर्देशन या सहयोजन शासकीय राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दिया जाता ।

(4) यदि सरकार यह समझती है कि किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य का पद पर बने रहना बोर्ड के हित में नहीं है, तो सरकार उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसके नामनिर्देशन को समाप्त करने का आदेश दे सकेगी और तत्पश्चात्, इस बात के होते हुए भी कि उस अवधि का अवसान नहीं हुआ है जिसके लिए कि वह नाम निर्दिष्ट था, वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

(5) बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा। त्याग-पत्र अध्यक्ष द्वारा उसके स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(6) मृत्यु, त्यागपत्र या सदस्य के नामनिर्देशन के पर्यवसान के कारण या किसी अन्य कारणवश किसी आकस्मिक रिक्ति के होने पर, ऐसी रिक्ति, यथास्थिति, निर्वाचन, नामनिर्देशन या सहयोजन द्वारा भरी जाएगी और ऐसी रिक्ति को भरने के लिए ऐसा निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट या सहयोजित व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो उस व्यक्ति के लिए मान्य थी जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट या सहयोजित किया गया है।

(7) पदावरोही सदस्य, पुनः निर्वाचन, पुनः नाम निर्देशन या पुनः सहयोजन का पात्र होगा।

(8) प्रत्येक निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट या सहयोजित व्यक्ति का नाम शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

गणपूर्ति।

7. बोर्ड की बैठक में कामकाज का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम सात सदस्य उपस्थित न हों।

रिक्तियों और अनियमितताओं के कारण कार्यवाहियों का अधिमान्य न होना।

8. धारा 7 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड या उसकी किसी समिति की कोई कार्यवाही या कार्यवाही केवल इसके सदस्यों की किसी विद्यमान रिक्ति के कारण या इसके गठन की किसी त्रुटि या मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाली प्रक्रिया की अनियमितता के कारण अधिमान्य नहीं होगी।

सदस्यों का विचार-विमर्श में भाग लेने से विवर्जित किया जाना।

9. कोई भी सदस्य किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित विचार-विमर्श में भाग नहीं लेगा या अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा, जिसमें कि उसका व्यक्तिगत या धन सम्बन्धी हित है।

बोर्ड की बैठक।

10. (1) बोर्ड, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में, उनमें गणपूर्ति सहित कामकाज के संव्यवहार में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो इस निमित्त बनाई गई उप-विधियों द्वारा उपबन्धित की जाए।

(2) अध्यक्ष, और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। इन दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) बोर्ड की बैठक में उद्भूत समस्त प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा; और मत बराबर होने की दशा में, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

11. राज्य सरकार बोर्ड को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करने के लिए, बोर्ड का एक सचिव नियुक्त करेगी। बोर्ड का सचिव।

12. इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्य होंगे :- बोर्ड के कृत्य और कर्तव्य।

- (i) संस्थाओं को संबद्ध करना और इस द्वारा संचालित परीक्षाओं के प्रचालन के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण विहित करना ;
- (ii) संबद्ध संस्थाओं के भवनों और उपस्कर के लिए मानक विहित करना ;
- (iii) संबद्ध संस्थाओं के कर्मचारीवृन्द के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अन्य स्तरमान विहित करना ;
- (iv) संबद्ध संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए शैक्षिक अर्हताएं विहित करना ;
- (v) संबद्ध संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश की रीति विहित करना ;
- (vi) इस द्वारा संचालित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का प्रवेश ;
- (vii) निचली से ऊंची श्रेणियों में उन्नत करने के लिए और डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षाएं संचालित करना ;
- (viii) इस द्वारा संचालित परीक्षाओं के परिणामों को प्रकाशित करना ;
- (ix) उन छात्रों को, जिन्होंने किसी संबद्ध संस्था में विहित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और इस द्वारा संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया है, प्रमाण-पत्र और डिप्लोमे देना ;
- (x) अन्य प्राधिकरणों और निकायों के साथ, ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों, सहयोग देना ;
- (xi) राज्य सरकार की तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास और उससे सम्बन्धित प्रशिक्षण पर सलाह देना ;
- (xii) अन्य समस्त ऐसी कार्यवाही और कार्य करना जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन इसके कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक हों ; और
- (xiii) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन इस पर अधिरोपित किए जाएं।

13. (1) बोर्ड को, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन इसके कृत्यों के निर्वहन और कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हैं। बोर्ड की शक्ति।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

- (i) अभ्यर्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसकी किसी परीक्षा को रद्द करना या अभ्यर्थी के किसी परीक्षा परिणाम को विधार्जित करना, या उसे आगामी परीक्षा में बैठने से अननुज्ञात करना, जिसे वह—

- (क) परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग; या
 - (ख) संस्था या परीक्षा के लिए प्रवेश के आवेदन-पत्र में मिथ्या कथन करने या तात्त्विक जानकारी छिपाने; या
 - (ग) परीक्षा में कपट या प्रतिरूपण, या
 - (घ) ऐसी परीक्षा में प्रवेश विनियमित करने वाले नियमों के उल्लंघन में परीक्षा में प्रवेश सुनिश्चित करना; या
 - (ङ) परीक्षा के दौरान घोर अनुशासनहीनता की किसी कार्रवाई का दोषी पाता है;
- (ii) परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता की किसी कार्रवाई के इस द्वारा दोषी पाए जाने वाले किसी अभ्यर्थी के परीक्षा अंकों में कटौती करना ;
- (iii) खण्ड (i) के उप-खण्ड (क) से (ङ) तक उल्लिखित सभी या किसी कार्रवाई के लिए इस द्वारा दोषी पाने या परिणाम घोषित करने में बोर्ड की सद्भाविक गलती के लिए किसी अभ्यर्थी के परीक्षा परिणाम को रद्द करना :

परन्तु बोर्ड को सद्भाविक गलती के आधार पर परीक्षा परिणाम परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के अवसान के पश्चात् रद्द नहीं किया जाएगा ;

- (iv) इस द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए फीस विहित करना और उसकी वसूली की रीति का उपबन्ध करना ;
- (v) किसी संस्था को संबद्ध करने से इन्कार करना जो :—
 - (क) इस निमित्त बोर्ड द्वारा कर्मचारीवृन्द, शिक्षण, उपस्कर या भवन के लिए अधिकथित स्तर को पूरा नहीं करती है, या पूरा करने की स्थिति में नहीं है या नहीं हो सकती है ; या
 - (ख) इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिकथित शर्तों का पालन नहीं करती है या करने की इच्छुक नहीं है ;
- (vi) बोर्ड द्वारा कर्मचारीवृन्द, शिक्षण, उपस्कर या भवन के लिए अधिकथित स्तर को बनाए रखने या उसके उपबन्ध करने में असमर्थ रहने या बोर्ड के समाधान के अनुसार संबद्ध करने की शर्तों के अनुपालन में इसके असमर्थ रहने पर किसी संस्था को उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् संबद्ध किए जाने से प्रत्याहृत करना ;
- (vii) नियमों या विनियमों या बोर्ड के विनिश्चयों, अनुदेशों या निदेशों के उल्लंघन में की गई किसी कार्रवाई के सम्बन्ध में संबद्ध संस्थाओं के प्रमुखों से रिपोर्ट मंगवाना और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विहित को जाए, नियमों या विनियमों या बोर्ड के विनिश्चयों, अनुदेशों या निदेशों के प्रवर्तन के लिए यथोचित कार्रवाई करना ;
- (viii) विहित पाठ्यक्रमों के सम्यक् अनुपालन को सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने कि शिक्षण के लिए सुविधाएँ सम्यक् रूप से प्रदान की जा रही हैं और उनका उपभोग किया जा रहा है, के प्रयोजनार्थ किसी संबद्ध संस्था का निरीक्षण करना; और

(ix) संबद्ध संस्था के पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों की अधिकतम संख्या निर्धारित करना।

(3) उप-धारा (1) और (2) में उल्लिखित सभी मामलों में बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा।

14. (1) राज्य सरकार को, बोर्ड द्वारा संचालित या किए गए किसी कार्य के संदर्भ में बोर्ड को सम्बोधित करने और बोर्ड से संबद्ध किसी मामले में बोर्ड को अपने विचार संसूचित करने का अधिकार होगा। राज्य सरकार की शक्तियाँ।

(2) बोर्ड, उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त संसूचना पर, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जैसी इस द्वारा को जानी प्रस्तावित हो या की गई हो उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और यदि यह कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो उसका स्पष्टीकरण देगा।

(3) यदि बोर्ड, उस मामले के संदर्भ में, जिस पर उप-धारा (1) के अधीन संसूचना प्राप्त की गई है, युक्तियुक्त, समय के भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है, तो राज्य सरकार, बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जैसे वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(4) किसी आपात स्थिति में, जिसमें राज्य सरकार की राय में तुरन्त कार्रवाई करना अपेक्षित हो, राज्य सरकार, बोर्ड से पूर्व परामर्श किए बिना, इस अधिनियम से संगत ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे और उसके बारे में बोर्ड को तुरन्त सूचित करेगी।

(5) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, उसके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, बोर्ड में बोर्ड के किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन को उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् निलम्बित कर सकेगी और बोर्ड द्वारा किए जाने के लिए आदिष्ट या आदिष्ट किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा संकल्प, आदेश या कार्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बोर्ड की प्रदत्त शक्तियों के बाहर है।

15. (1) बोर्ड, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा और उन्हें राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर सकेगा। राज्य सरकार विनियमों को अनुमोदित, उपांतरित या उसमें फेर-फार कर सकेगी। राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विनियम, राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और प्रकाशन की तारीख से, और जहाँ तारीख विनिर्दिष्ट की गई हो, उस तारीख से प्रभावी होंगे।

विनियम बनाने की शक्ति।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा :-

- (क) इस अधिनियम के अधीन गठित समितियों और उप-समितियों की नियुक्ति, गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ;
- (ख) प्रमाण-पत्रों और डिप्लोमाओं को प्रदान किए जाने की रीति और शर्तें ;
- (ग) संस्थाओं को संबद्ध करने की शर्तें ;

- (घ) प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा की परीक्षाओं के लिए विहित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;
- (ङ) बोर्ड की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के प्रवेश और प्रमाण-पत्रों और डिप्लोमाओं की पात्रता के लिए शर्तें ;
- (च) बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए फीस और उनकी वसूली की रीति ;
- (छ) परीक्षाओं का संचालन ;
- (ज) परीक्षकों, अनुसूचीकों, मिलानकर्ताओं, जांचकर्ताओं, सारणीयकों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र अधीक्षकों और निरीक्षकों की नियुक्ति और बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में उनके कर्त्तव्य और शक्तियाँ, और उनके पारिश्रमिक की दरें ;
- (झ) संबद्धता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए उनके भू-आनुषंगिक (अपटिनेंट) सहित भवनों, आवश्यक उपकरणों और उपकरणों के मानक ;
- (ञ) बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं के परिणामों का प्रकाशन ;
- (ट) संबद्ध संस्था में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ ;
- (ठ) संबद्ध संस्था में विद्यार्थियों का प्रवेश ;
- (ड) विहित पाठ्यक्रमों के उचित अनुपालन और शिक्षण की सुविधाओं को सम्यक् रूप से दिए जाने और लाभ उठाए जाने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से संबद्ध संस्थाओं का निरीक्षण ;
- (ढ) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन अभ्यर्थी का संबद्ध संस्था के पाठ्यक्रम में बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश अस्वीकृत किया जा सके ;
- (ण) बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा के परिणाम को रोकना या रद्द करना और किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में इस द्वारा संचालित परीक्षा को रद्द करना ;
- (त) परिस्थितियाँ, जिनके अधीन संस्था की संबद्धता वापस ली जा सके या उससे इन्कार किया जा सके ;
- (थ) केन्द्र का निरीक्षण ; और
- (द) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किया जाना हो या विहित किया जा सके ।

उप-विधियाँ
बनाने की
शक्ति ।

16. (1) बोर्ड, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए उप-विधियाँ बना सकेगा ।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी उप-विधियाँ निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगी :-

- (क) प्रक्रिया, जिसका बोर्ड की बैठकों में अनुपालन किया जाना हो ;
- (ख) बोर्ड, समिति या उप-समिति की बैठक की तारीख और कामकाज की सूचना जिस पर इस बैठक में विचार होना है, बोर्ड के सदस्यों को देने और ऐसी बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने ; और
- (ग) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जा सकेगा ।

17. एक बोर्ड-निधि का गठन किया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राशियाँ उसके जमाखाने में रखी जाएंगी । बोर्ड-निधि का गठन ।

18. (1) दिन-प्रतिदिन व्यय के लिए अपेक्षित धन के सिवाय, बोर्ड निधि के खाते में जमा समस्त धन, अनुसूचित बैंक में खालू या बचत लेखा में रखा जाएगा : अभिरक्षा और विनिधान ।

परन्तु इस धारा की कोई भी बात बोर्ड को किसी ऐसे धन का विनिधान करने से, जो किसी सरकारी प्रतिभूति या किसी अनुसूचित बैंक में सावधि निक्षेप में तुरन्त व्यय के लिए अपेक्षित नहीं है, प्रवारित नहीं करेगी ।

1934 का 2

स्पष्टीकरण:—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, “अनुसूचित बैंक” से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक अभिप्रेत है ।

(2) बैंक में बोर्ड का खाता, बोर्ड के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा, जिन्हें बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, प्रचालित किया जा सकेगा ।

19. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड-निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोजन किया जाएगा :— बोर्ड-निधि का उप-योजन ।

- (i) इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट विभिन्न मामलों से सम्बन्धित या आनुषंगिक प्रश्नों और व्ययों के संचय मात्र के लिए ; और
- (ii) किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए जिनके वास्ते इस अधिनियम द्वारा या के अधीन बोर्ड को शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं या कर्तव्य अधिरोपित किए जाते हैं ।

20. बोर्ड के लेखाओं की लेखा-परीक्षा प्रतिवर्ष ऐसे अभिकरण द्वारा की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और संपरीक्षित लेखाओं और तुलनपत्र की प्रति, बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार को प्रतिवर्ष उस तारीख तक प्रस्तुत की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । बोर्ड के लेखाओं की लेखा-परीक्षा ।

21. बोर्ड की सभी लिखित संविदाएं और हस्तान्तरण-पत्र, बोर्ड की ओर से सचिव द्वारा या ऐसी अन्य रीति से, जैसी विहित की जाए, हस्ताक्षरित होंगे और यदि वे उक्त रीति से हस्ताक्षरित हों तो बोर्ड पर आवद्धकर होंगे । संविदाएं ।

22. इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :— बोर्ड के अधिकारी ।

1. अध्यक्ष ;
2. उपाध्यक्ष ;
3. बोर्ड का सचिव ; और
4. ऐसे अन्य अधिकारी जो बोर्ड के अधिकारी होने के लिए विनियमों द्वारा घोषित किए जाएं ।

अध्यक्ष ।

23. (1) राज्य सरकार, सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविदों या प्रशासनिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट या नियुक्त करेगी जो सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) यदि अध्यक्ष,—

(क) अधिनियम के उपबन्धों को जानबूझ कर कार्यान्वित करने से इनकार करता है, या

(ख) उसमें विहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या

(ग) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि कार्यालय में अध्यक्ष का बने रहना बोर्ड के हितों के लिए अहितकर है,

तो सरकार उसे मुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश द्वारा अध्यक्ष को हटा सकेगी ।

(3) अध्यक्ष की सेवाओं को, उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व भी, किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार सरकार को प्राप्त होगा ।

अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य ।

24. (1) अध्यक्ष, बोर्ड का प्रशासनिक प्रमुख होगा । यह देखना अध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है और उसको इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

(2) अध्यक्ष, किसी भी समय, और विहित अंतराल में, या बोर्ड के सदस्यों द्वारा, जो उसके सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई संख्या से कम न हो, हस्ताक्षरित अध्यक्षता की प्राप्ति पर और बोर्ड के समक्ष रखे जाने वाले कार्य को स्पष्ट करते हुए, विहित रीति में, बोर्ड की बैठक बुलाएगा ।

(3) अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्य के कारण उत्पन्न हुई आपात स्थिति में, जिस पर उसके विचार में तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् इस कार्रवाई की सूचना बोर्ड को उसकी अगली बैठक में देगा ।

(4) अध्यक्ष, उस प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें वह उपस्थित हो ।

(5) अध्यक्ष, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं ।

उपाध्यक्ष ।

25. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष होगा ।

उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य ।

26. उपाध्यक्ष, सभी प्रशासनिक और शैक्षिक विषयों में अध्यक्ष की सहायता करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं और पश्चात्कथित की अनुपस्थिति में वह अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

सचिव की शक्तियाँ और कर्तव्य ।

27. (1) सचिव, अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा ।

(2) बोर्ड की समस्त बैठकें, विनियमों द्वारा उपबन्धित रीति में, सचिव के माध्यम से बुलाई जाएंगी ।

(3) सचिव, यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाए जिनकी बाबत यह स्वीकृत या आबंटित किया गया था।

(4) सचिव, बोर्ड की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) सचिव, बोर्ड की किसी भी बैठक में उपसंजात होने और बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह बैठक में मत देने का हकदार नहीं होगा।

(6) सचिव, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा अधि-कथित की जाएं।

28. (1) राज्य सरकार, बोर्ड के उप-सचिवों और ऐसी सहायक सचिवों की नियुक्ति ऐसी शर्तों पर ऐसी अवधि के लिए कर सकेगी जो वह उचित समझे।

बोर्ड के
अन्य कर्म-
चारी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो विहित की जाएं।

(3) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकेगा जिन्हें वह इसके कृत्यों का दक्षतापूर्ण अनुपालन करने के लिए उचित समझे।

(4) सचिव/उप-सचिव और सहायक सचिव से भिन्न बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें और वेतनमान विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

29. (1) बोर्ड, इसके किसी उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए ऐसी समितियों नियुक्त कर सकेगा जो उचित समझी जाएं।

समितियों
की नियुक्ति
और गठन।

(2) प्रत्येक ऐसी समिति का गठन, बोर्ड के ऐसे सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से, यदि कोई हों, होगा जो बोर्ड उचित समझे।

(3) प्रत्येक ऐसी समिति, उसके लिए नियुक्त सदस्यों की एक-तिहाई संख्या तक, बोर्ड के सदस्यों में से समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकेगी।

(4) सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।

30. इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से सम्बन्धित सभी मामले, जिन्हें बोर्ड द्वारा धारा 29 के अधीन नियुक्त किसी समिति को विनियमों द्वारा प्रत्यायोजित किया गया है, उस समिति को निर्दिष्ट हो जाएंगे और बोर्ड ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा।

बोर्ड द्वारा
समितियों को
प्रत्यायोजित
शक्तियों का
प्रयोग।

परन्तु जहां बोर्ड की राय में, किसी ऐसे मामले में तुरन्त कार्रवाई की जानी आवश्यक है, वहां वह ऐसी कार्रवाई समिति की रिपोर्ट के बिना ही कर सकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

31. (1) प्रथम विनियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और बोर्ड द्वारा बनाए हुए समझे जाएंगे और ये तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक बोर्ड द्वारा परिवर्तित या उपांतरित नहीं कर दिए जाते।

बोर्ड के
प्रथम विनि-
यम।

(2) उप-धारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक उन्हें शासकीय राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर दिया जाता।

32. धारा 15 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम, या उसके प्रत्येक रूपांतर या संशोधन या धारा 31 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए या बनाए हुए समझे गए प्रथम विनियमों की प्रति असम्यक् विलम्ब के बिना सरकार को उसकी जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

विनियमों
की प्रतियां
और उनका
परिवर्तन।

अधिनियम
के प्रारम्भ
होने पर
परिणाम।

33. धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना में बोर्ड की स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट तारीख, से निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावो होंगे, अर्थात् :-

- (i) इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, तकनीकी शिक्षा की बाबत हिमाचल प्रदेश में स्थित समस्त तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं को जिन्हें हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा विशेषाधिकार दिए गए हैं, ऐसी तकनीकी शिक्षा की बाबत, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से बोर्ड के विशेषाधिकार दिए हुए समझे जाएंगे और बोर्ड, यथासंभव इस अधिनियम से संगत, तकनीकी शिक्षा की बाबत ऐसी संस्थाओं को ऐसे समस्त विशेषाधिकार देगा जो उन्हें उक्त तारीख से पूर्व हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए होते; और
- (ii) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी बोर्ड, हिमाचल प्रदेश में स्थित संस्थाओं के विद्यार्थियों और जिन्होंने विशेषाधिकार प्राप्त हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड में प्रवेश लिया है और इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व तकनीकी शिक्षा में उक्त बोर्ड की परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे हैं या इसके पात्र हैं, उक्त बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार उनके शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए और ऐसे अन्य विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में उपबन्ध करेगा, जो विहित की जाए।

कठिनाइयों
के निरा-
करण की
शक्ति।

34. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को, कार्यान्वित करने में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन नियम या विनियम द्वारा विनियमित किए जाने वाले विषय को आदेश द्वारा विनियमित कर सकेगी।

बोर्ड की
वार्षिक और
लेखा परीक्षा
रिपोर्टों का
प्रस्तुत किया
जाना।

35. (1) बोर्ड, वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में ऐसे समय पर जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के, उसके कार्यकलाप का सही और पूर्ण विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी।

(2) धारा 20 के अधीन बोर्ड की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के तुरन्त पश्चात् राज्य सरकार उक्त रिपोर्टों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी:

परन्तु जब रिपोर्ट बजट सत्र में प्रस्तुत की जानी हो, तो उक्त सत्र की प्रथम बैठक में सभा पटल पर रखी जाएगी:

परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे रिपोर्ट सम्बन्धित है और रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के बीच की अवधि नौ मास से अधिक नहीं होगी।

नियम बनाने
की शक्ति।

36. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और शासकीय राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

(क) बोर्ड, समितियों और उप-समितियों के सदस्यों और उनमें सहयोजित व्यक्तियों को संदेय यात्रा और दैनिक भत्तों की दरें और उनके भुगतान की रीति;

- (ख) बोर्ड, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और सचिव की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य;
और
- (ग) कोई अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाए।

37. राज्य सरकार द्वारा क्रमशः धारा 36 या धारा 31 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम या प्रथम विनियम या धारा 34 के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश और बोर्ड द्वारा धारा 16 और 32 के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम या उप-विधि, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में, दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है और यदि उस सत्र के जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या उपर्युक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उसमें कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाए या इस बारे में सहमत हो जाए कि यह नहीं बनाया जाना चाहिए तो, यथास्थिति, नियम, विनियम, उप-विधि या आदेश, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु ऐसे उपान्तरण या वातिलीकरण से उस नियम, विनियम, उप-विधि या आदेश के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्य वि-
धान सभा
के समक्ष रखे
जाने वाले
परिनियम,
विनियम
और कतिपय
आदेश।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Takniki Shiksha Board Adhiniyam, 1986 (1986 Ka Adhiniyam Sankhyank 14) as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

Act No. 14 of 1986.

THE HIMACHAL PRADESH TAKNIKI SHIKSHA BOARD ACT, 1986

(AS ASSENTED BY THE GOVERNOR ON 3RD MAY, 1986

AN

ACT

to provide for the establishment and constitution of a Takniki Shiksha Board in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith.

BE it enacted by the Himachal Pradesh Legislative Assembly in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title,
extent and
commence-
ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Takniki Shiksha Board Act, 1986.

(2) It shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “affiliated institution” means an institution affiliated to the Board in respect of any course or courses of study in accordance with the provisions of the Act or regulations made thereunder;
- (b) “Board” means the Himachal Pradesh Takniki Shiksha Board established under section 3;
- (c) “bye-laws” means bye-laws made by the Board under this Act;
- (d) “centre” means the institution or the place fixed by the Board for the purpose of holding its examinations and includes the premises attached or appurtenant thereto;
- (e) “certificate” means the certificate awarded by the Board to a person for successfully completing in an affiliated institution such courses of study as may from time to time be prescribed by regulations;
- (f) “Chairman” means the Chairman of the Board;
- (g) “diploma” means a diploma awarded by the Board to a person for successfully completing in an affiliated institution such courses of study as may from time to time be prescribed by regulations;
- (h) “director” means the Director of Technical Education, Vocational and Industrial Training, Himachal Pradesh;
- (i) “industrial training” means training imparted to students in Industrial Training Institutions;
- (j) “institution” means institution imparting technical education and industrial training;

- (k) "invigilator" means a person who assists the Superintendent of a centre in conducting and supervising the examination at the centre and includes a project observer in relation to a project examination;
- (l) "member" means a member of the Board and includes the Chairman and the Vice-Chairman thereof;
- (m) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;
- (n) "Principal" means the Head of the Institution;
- (o) "regulation" means regulation made by the Board under this Act;
- (p) "Secretary" means the Secretary to the Board;
- (q) "State" means the State of Himachal Pradesh;
- (r) "Superintendent of centre" means the person appointed by the Board to conduct and supervise examination of the Board and includes an Additional Superintendent and an Associate Superintendent;
- (s) "technical education" means the education imparted to students in the technical institutions ; and
- (t) "Vice-Chairman" means the Vice-Chairman of the Board.

3. (1) There shall be established by the State Government by notification in the Official Gazette a Board to be called "THE HIMACHAL PRADESH TAKNIKI SHIKSHA BOARD" and, such a notification may be made notwithstanding the fact that one or more of the seats of members are yet to be filled.

Establishment of the Board.

(2) The Board incorporated under sub-section (1) shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire and hold property, both movable and immovable, to transfer any property held by it, enter into contracts and to do all other things necessary for the purpose of its constitution and may sue or be sued in its corporate name.

4. (1) The Board shall consist of the Chairman, the Vice-Chairman and the following members, namely:—

Constitution of the Board.

I. Ex-officio Members:

- (i) one representative of the Ministry for the time being dealing with technical education in the Government of India;
- (ii) one representative of the Northern Regional Committee of All India Council of Technical Education;
- (iii) the Secretary (Technical Education) to the Government of Himachal Pradesh;
- (iv) the Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh;
- (v) the Labour Commissioner, Himachal Pradesh;
- (vi) the Director of Industries, Himachal Pradesh;
- (vii) the Registrar, Himachal Pradesh University;
- (viii) the Principal, Regional Engineering College, Hamirpur, Himachal Pradesh;

II. Elected Members:

- (ix) two persons elected by the Himachal Pradesh Vidhan Sabha from amongst its members in the manner prescribed by the Speaker;

III. Nominated Members: (to be nominated by the State Government)

- (x) one Chief Engineer of the Public Works Department, Himachal Pradesh Government;
- (xi) one Chief Engineer, Himachal Pradesh State Electricity Board;
- (xii) two industrialists;
- (xiii) one Principal of Polytechnics in the State;
- (xiv) one Principal of Industrial Training Institutes in the State;
- (xv) one member to secure representation of such interests as are not otherwise represented;

IV. Co-opted Members:

- (xvi) one member to be co-opted by the Board for his expert and wide knowledge of technical education.

(2) The members mentioned in sub-clauses (iii) and (iv) of sub-section (1) may, instead of attending any meeting of the Board themselves, depute any officer subordinate to them, not below the rank of the Under Secretary to the Government of Himachal Pradesh and the officers so deputed shall be entitled to take part in the proceedings of the particular meeting for which they are deputed and shall also be entitled to vote at such meeting.

Headquarters of the Board.

5. The Board shall have its headquarters at a place to be notified by the State Government in the Official Gazette.

Term of office of members and filling of casual vacancies.

6. (1) The term of the office of members other than *ex-officio* members shall be three years.

(2) If any elected member ceases for any reason to be a member of the Legislative Assembly from which he was elected, he shall cease to be a member and his office shall become vacant.

(3) Notwithstanding anything contained in this section, an outgoing member shall, unless the Government otherwise directs, continue in office until the election, nomination or co-option of his successor is notified in the Official Gazette.

(4) If the Government considers that the continuance in office of any nominated member is not in the interest of the Board, the Government may, after giving him reasonable opportunity of being heard, make an order terminating his nomination and thereupon he shall cease to be a member of the Board notwithstanding that the term for which he was nominated has not expired.

(5) Any member of the Board may resign his office by a letter addressed to the Chairman. The resignation shall take effect from the date of acceptance of his resignation by the Chairman.

(6) In the event of a casual vacancy occurring by reason of death, resignation or termination of nomination of a member or for any other reason, such vacancy shall be filled by election, nomination, or co-option, as the case may be, and any person so elected, nominated or co-opted to fill such vacancy shall hold office for the term for which it was tenable by the person in whose place he has been so elected, nominated or co-opted.

(7) An outgoing member shall be eligible for re-election, re-nomination or re-co-option.

(8) The name of every person elected, nominated or co-opted shall be notified in the Official Gazette.

7. No business shall be transacted at a meeting of the Board unless at least seven members are present.

Quorum.

8. Subject to the provisions contained in section 7, no act or proceeding of the Board or a committee thereof shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy among its members or by reason of a defect in its constitution or an irregularity in procedure not affecting the merits of the case.

Proceedings not to be invalidated by reasons of vacancies and irregularities.e

9. No member shall take part in the discussion of, or exercise his vote on, any matter in which he has any personal or pecuniary interest.

Members debarred from taking part in discussion.

10. (1) The Board shall meet at such times and places and shall observe such procedure in transacting the business at its meetings, including the quorum thereat, as may be provided by bye-laws made in this behalf.

Meeting of the Board.

(2) The Chairman, and in his absence, the Vice-Chairman, shall preside at the meetings of the Board. In the absence of both, any member chosen by the members present in the meeting shall preside at that meeting.

(3) All questions arising in a meeting of the Board shall be decided by majority of votes of the members present and voting and, in case of equality of votes, the person presiding at such meeting shall have a second or casting vote.

11. The State Government shall appoint a Secretary to the Board to assist the Board in carrying out the purposes of this Act.

Secretary of the Board.

12. Subject to the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder, the functions and duties of the Board shall be—

Functions and duties of the Board.

- (i) to affiliate institutions and prescribe courses of study and instructions leading to examinations conducted by it;
- (ii) to prescribe standards for buildings and equipment of affiliated institutions;
- (iii) to prescribe educational qualifications and other standards for the members of the staff of the affiliated institutions;

- (iv) to prescribe educational qualifications for admission of students to affiliated institutions;
- (v) to prescribe the manner of admission of students to affiliated institutions;
- (vi) to admit candidates to examinations conducted by it;
- (vii) to conduct examinations for promotion from lower to higher classes and also for awarding certificates and diplomas;
- (viii) to publish results of examinations conducted by it;
- (ix) to grant certificates and diplomas to students who have completed the prescribed course of study in an affiliated institution and have passed the examinations conducted by it;
- (x) to co-operate with other authorities and bodies in such manner and for such purposes as may be necessary for giving effect to the provisions of this Act;
- (xi) to advise the State Government on co-ordinated development of technical education and training regarding the same;
- (xii) to do all other such acts and things as may be necessary for the proper discharge of its functions under this Act or the rules or regulations made thereunder; and
- (xiii) to carry out such other duties as may be imposed upon it under this Act or the rules or regulations made thereunder.

Power of
the Board.

13. (1) The Board shall, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, have all such powers as may be necessary for the discharge of its functions and the performance of its duties under this Act and or regulations made thereunder.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Board shall have the powers—

- (i) after giving the candidate a reasonable opportunity of being heard, to cancel an examination, or withhold the result of an examination, of a candidate, or to disallow him from appearing at any future examination who is found by it to be guilty of—
 - (a) using unfair means in the examination;
 - (b) making any incorrect statement or suppressing material information or fact in the application form for admission to the institution or to the examination;
 - (c) fraud or impersonation at the examination;
 - (d) securing admission to the examination in contravention of the rules governing admission to such examination; or
 - (e) any act of gross indiscipline in the course of the examination;
- (ii) to deduct marks at any examination of any candidate found by it to be guilty of any act of indiscipline in the course of the examination;
- (iii) to cancel the result of an examination of any candidate found by it to be guilty of all or any of the acts mentioned in sub-clauses (a) to (d) of clause (i) or for any *bonafide* error of the Board in the declaration of the result:

Provided that the result of an examination shall not be cancelled on the ground of a *bonafide* error of the Board, after the expiry of 90 days from the date of announcement of the result of the examination;

(iv) to prescribe fees for the examinations conducted by it and provide for the manner of their realisation;

(v) to refuse affiliation of an institution—

(a) which does not fulfil, or is not in a position to fulfil or does not come upto the standards for staff, instruction, equipment or buildings laid down by the Board in this behalf ; or

(b) which does not or is not willing to abide by the conditions of affiliation laid down by the Board in this behalf ;

(vi) after giving the institution concerned a reasonable opportunity of being heard, to withdraw affiliation of an institution not able to adhere to or make a provision for standards of staff, instruction, equipment or buildings laid down by the Board, or on its failure to observe the conditions of affiliation to the satisfaction of the Board;

(vii) to call for reports from the heads of affiliated institutions in respect of any act done in contravention of the rules or regulations or decisions, instructions or directions of the Board, and take suitable action for the enforcement of the rules or regulations or decisions, instructions or directions of the Board, in such manner as may be prescribed by the regulations;

(viii) to inspect an affiliated institution for the purpose of ensuring due observance of the prescribed courses of study and to ensure that facilities for instructions are duly provided and availed of ; and

(ix) to fix the maximum number of students that may be admitted to courses of study in an affiliated institution.

(3) The decision of the Board in all matters mentioned in sub-sections (1) and (2) shall be final.

14. (1) The State Government shall have the right to address the Board with reference to anything conducted or done by the Board and to communicate to the Board its views on any matter with which the Board is concerned.

Powers of
the State
Government.

(2) The Board shall report to the State Government such action, if any, as it proposes to take or has taken upon the communication received under sub-section (1) and shall furnish an explanation if it fails to take action.

(3) If the Board does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government with reference to the matter on which a communication has been received under sub-section (1), the State Government may, after considering the explanation furnished or representation, if any, made by the Board, issue such directions consistent with this Act, as it may think fit and the Board shall comply with such directions.

(4) In any emergency which in the opinion of the State Government, requires that immediate action should be taken, the State Government may take such action consistent with this Act as it deems necessary, without previous consultation with the Board and shall forthwith inform the Board thereof.

(5) The State Government may, after giving the Board a reasonable opportunity of being heard and by order in writing specifying the reasons therefor, suspend the execution of any resolution or order of the Board and prohibit the doing of any act ordered or purporting to be ordered to be done by the Board if the State Government is of the opinion that such resolution, order or act is in excess of the powers conferred by or under this Act upon the Board.

Power to
make regu-
lations.

15. (1) The Board may, for carrying out the purposes of this Act, make regulations consistent with the provisions of this Act and the rules framed thereunder and submit the same for approval of the State Government. The State Government may approve, modify or vary the regulations. The regulations, as approved by the State Government, shall be published in the Official Gazette and shall take effect from the date of publication, and where a date has been specified from that date.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the regulations may provide for—

- (a) the appointment, constitution, powers and duties of the committees and sub-committees constituted under this Act;
- (b) the manner and conditions of conferment of certificates and diplomas;
- (c) the conditions for affiliation of institutions;
- (d) the courses of study to be prescribed for certificate and diploma examinations;
- (e) the conditions under which candidates shall be admitted to the examinations of the Board and shall be eligible for certificates and diplomas;
- (f) the fees for admission to the examinations of the Board and the manner of their realisation;
- (g) the conduct of examinations;
- (h) the appointment of examiners, moderators, collators, scrutini-
zers, tabulators, centre inspectors, superintendents of centres and
invigilators, and their duties and powers in relation to the Board's
examinations, and the rates of their remuneration;
- (i) standards for buildings including land, appurtenant thereto, the
equipment and apparatus necessary for institutions seeking affilia-
tion;
- (j) publication of results of examinations conducted by the Board;
- (k) the minimum educational and other qualifications for admission
of students to an affiliated institution;
- (l) admission of students to affiliated institutions;
- (m) the inspection of affiliated institutions with a view to ensuring
due observance of the prescribed courses of study and that faci-
lities for instruction are duly provided and availed of;
- (n) the conditions under which a candidate may be disallowed ad-
mission to the examination of the Board in courses of study in
an affiliated institution;
- (o) withholding or cancelling results of an examination conducted by the
Board and cancelling an examination conducted by it in respect
of any candidate;
- (p) the circumstances under which affiliation of an institution may be
withdrawn or refused;
- (q) inspection of a centre; and

(r) any other matter which under this Act or rules made thereunder is to be or may be prescribed by regulations.

16. (1) The Board may make bye-laws for giving effect to the provisions of this Act and the rules and the regulations made thereunder.

Power to make bye-laws.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such bye-laws may provide for—

- (a) the procedure to be observed at meetings of the Board;
- (b) the giving of notice to members of the Board, a committee or a sub-committee of the date of a meeting and of the business to be considered thereat, and for the keeping of the record of proceedings of such meeting; and
- (c) any other matter which, under this Act or the rules or regulations made thereunder, is to be or may be prescribed by bye-laws.

17. A Board Fund shall be constituted and all sums received by or on behalf of the Board under this Act or otherwise shall be placed to the credit thereof.

Constitution of Board Fund.

18. (1) All moneys at credit of the Board Fund, except moneys required for day-to-day expenditure, shall be kept in the Current or Savings Accounts with a Scheduled Bank:

Custody and investment.

Provided that nothing in this section shall be deemed to preclude the Board from investing such moneys as are not required for immediate expenditure in any of the Government securities or in fixed deposits in a Scheduled Bank.

Explanation.—For the purposes of this sub-section “Scheduled Bank” means a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934.

(2) Accounts of the Board with a bank may be operated by the Secretary of the Board or by such other officers as may be specified by the Board.

19. Subject to the provisions of this Act, the Board Fund shall be applicable—

Application of Board Fund.

- (i) only to the payment of the charges and expenses in connection with or incidental to the several matters specified in this Act; and
- (ii) to any other purposes for which by or under this Act powers are conferred or duties are imposed upon the Board.

20. The accounts of the Board shall be audited annually by such agency as may be specified by the State Government and a copy of the audited accounts and balance sheet shall be submitted by the Board to the State Government each year by such date as the State Government may specify.

Audit of accounts of the Board.

Contracts.

21. All contracts in writing and assurances in respect of property of the Board shall be signed by the Secretary on behalf of the Board or in such other manner, as may be prescribed, and shall, if so signed, be binding on the Board.

Officers of the Board.

22. Subject to other provisions of this Act, the following shall be the officers of the Board, namely:—

- (1) the Chairman;
- (2) the Vice-Chairman;
- (3) the Secretary to the Board; and
- (4) such other officers as may be declared by the regulations to be the officers of the Board.

Chairman.

23. (1) The State Government shall nominate/appoint a person to be the Chairman of the Board from amongst eminent educationists or persons having administrative experience on such terms and conditions and for such period as may be prescribed by the Government.

(2) If the Chairman (a) wilfully omits or refuses to carry out the provisions of the Act, or (b) abuses the powers vested in him, or (c) if it appears to the Government that the continuance of the Chairman in office is detrimental to the interests of the Board, the Government may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, by order remove the Chairman.

(3) The Government will have the right to terminate the services of the Chairman at any time, even before the expiry of his term of office.

Powers and duties of the Chairman.

24. (1) The Chairman shall be the administrative head of the Board. It shall be the duty of the Chairman to see that this Act and the rules and regulations framed thereunder are strictly followed and he shall have all necessary powers for this purpose.

(2) The Chairman may, at any time, and shall at prescribed intervals or on receipt of a requisition signed by not less than one-third of the total number of members of the Board and stating the business to be brought before the Board, call a meeting of the Board in the prescribed manner.

(3) In any emergency, arising out of the administrative business of the Board, which, in the opinion of the Chairman, requires that immediate action should be taken, the Chairman shall take such action as he deems necessary and shall thereafter report that action to the Board at its next meeting.

(4) The Chairman shall preside at every meeting of the Board at which he is present.

(5) The Chairman shall exercise such other powers as may be vested in him by the regulations.

Vice-Chairman.

25. The Director of Technical Education, Himachal Pradesh, shall be the *ex-officio* Vice-Chairman of the Board.

Powers and duties of the Vice-Chairman.

26. The Vice-Chairman shall assist the Chairman in all matters, administrative and academic, and shall discharge such duties and exercise such powers as may be delegated to him by the Chairman, and shall in the latter's absence exercise all the powers of the Chairman.

27. (1) The Secretary shall, subject to control of the Chairman, be the Chief Executive Officer of the Board.

Powers and duties of the Secretary.

(2) All the meetings of the Board shall be convened through the Secretary in the manner provided by the regulations.

(3) The Secretary shall be responsible for ensuring that all moneys are expended for the purposes for which they are granted or allotted.

(4) The Secretary shall be responsible for keeping the minutes of all meetings of the Board.

(5) The Secretary shall be entitled to be present and to speak at any meeting of the Board but shall not be entitled to vote thereat.

(6) The Secretary shall exercise such other powers as may be laid down in the regulations.

28. (1) The State Government may appoint Deputy Secretaries to the Board and such number of Assistant Secretaries thereof, on such conditions and for such period as the Government may deem fit.

Other officers and servants of the Board.

(2) The officers appointed under sub-section (1) shall perform such functions and exercise such powers as may be prescribed.

(3) The Board may appoint such other officers and servants as it considers necessary for the efficient performance of its functions.

(4) The qualifications, conditions of service and scales of pay of officers and servants of the Board, other than Secretary/Deputy Secretary and Assistant Secretary shall be determined by the regulations.

29. (1) The Board may appoint such committees as are deemed proper for the furtherance of any of its objectives.

Appointment and constitution of committees.

(2) Every such committee shall consist of such members of the Board and of such other persons, if any, as the Board may think fit.

(3) Every such committee may co-opt persons to be members from amongst the members of the Board to the extent of one-third of the members appointed to it.

(4) The term of the members shall be as prescribed by regulations.

30. All matters relating to the exercise by the Board of powers conferred upon it by this Act which have, by regulations, been delegated by the Board to any committee appointed under section 29 shall stand referred to that committee, and the Board before exercising any such powers, shall receive and consider the report of the committee with respect to the matter in question:

Exercise of powers delegated by Board to Committees.

Provided that where, in the opinion of the Board, immediate action is necessary with respect to any such matter, it may proceed to deal with it without the report of the committee in respect thereof and pass such orders thereon as it considers necessary.

First regulations of the Board.

31. (1) The First Regulations shall be made by the State Government and they shall be deemed to have been made by the Board and continue in force until altered or modified by the Board.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall not take effect until these have been published in the Official Gazette.

Copies of regulations and alterations thereof.

32. A copy of every regulation made by the Board under section 15 and of every modification or revision thereof or of each of the First Regulations of the Board made or deemed to have been made under section 31 shall be submitted without undue delay to the Government for information.

Consequences to ensue on commencement of the Act.

33. As from the date specified for the establishment of the Board in the notification under sub-section (1) of section 3, the following provisions shall have effect, namely:—

(i) notwithstanding anything contained in this Act, all technical educational institutions admitted to the privileges of the State Board of Technical Education, Haryana in respect of technical education and situated within Himachal Pradesh shall in respect of such technical education, with effect from the date of commencement of this Act, be deemed to be admitted to the privileges of the Board, and the Board shall, as far as possible and consistent with this Act, admit such institutions to all such privileges in respect of technical education as they had from the State Board of Technical Education, Haryana before the said date; and

(ii) notwithstanding anything contained in this Act or the rules and regulations made thereunder, the Board shall provide for such period, and in such manner, as may be prescribed, for the instruction, teaching and training of students of institutions situated within Himachal Pradesh and admitted to the privileges of the State Board of Technical Education, Haryana who before the date of the commencement of this Act were studying or were eligible for the examination of the said Board in technical education and for examination of such students and others in accordance with the courses of studies of the said Board.

Power to remove difficulties.

34. The State Government may, with a view to remove any difficulty in giving effect to the provisions of this Act, regulate by order any matter which is to be regulated by a rule or regulation under this Act.

Laying of the annual and audit reports of the Board.

35. (1) The Board shall prepare once in a year, in such form at such times, as may be directed by the State Government, an annual report, giving a true and full account of its activities during the preceding year, and a copy thereof shall be forwarded to the State Government.

(2) Soon after the submission of the audit report under section 20 and the annual report under sub-section (1) of the Board, the State Government shall cause the said reports to be laid before the State Legislative Assembly:

Provided that when these reports are to be laid in the Budget Session, those shall be laid on the Table of the House on the first sitting of the said session:

Provided further that the period intervening between the close of the financial year to which the reports pertain and the laying of the reports shall not exceed nine months.

36. (1) The State Government may, by notification and after previous publication in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

Powers to make rules.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

- (a) the rates of travelling and daily allowances payable to members of the Board, committees and sub-committees and the persons co-opted thereto, and the manner of their payment;
- (b) the powers, duties and functions of the Board, the Chairman, the Vice-Chairman and the Secretary; and
- (c) any other matter which under this Act is to be or may be prescribed by rules.

37. Every rule, First Regulations or order made by the State Government under sections 36, 31 and 34, and every regulation or bye-law made by the Board under sections 16 and 32 shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in it or agrees that it should not be made, the rule, regulation, bye-law or order shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule, regulation, bye-law or order, as the case may be.

Statutes, regulations and certain orders to be laid before the State Legislative Assembly.

